



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12112022-240228  
CG-DL-W-12112022-240228

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2022 (कार्तिक 21, 1944)  
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2022 (KARTIKA 21, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	957	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	971	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3395	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	10703
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	461
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	2953
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक.....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	957	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	971	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	3395	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	10703
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	461
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	2953
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2022

संकल्प

विषय: भूजल आकलन पद्धति 2015 की समीक्षा और संशोधन के लिए भूजल संसाधन आकलन समिति का गठन (जीईसी-2015)

सं. टी-13014/1/2019-जीडब्ल्यू—भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गठित "भू जल संसाधन आकलन समिति (जीईसी)" द्वारा अनुशंसित कार्यप्रणाली के आधार पर समय-समय पर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य भूजल / नोडल विभागों द्वारा संयुक्त रूप से देश के भूजल संसाधन का आकलन किया जा रहा है। पहली "भूजल संसाधन आकलन समिति (जीईसी)" का गठन वर्ष 1984 में किया गया था, तत्पश्चात वर्ष 1997 और 2015 में नई प्रगति / प्रथाओं / उपकरणों को शामिल करने और आकलन में उपयोग किए जा रहे विभिन्न मानकों को परिष्कृत करने की कार्यप्रणाली की समीक्षा और संशोधन करने के लिए किया गया। देश के भूजल संसाधन का आकलन वर्ष 2004, 2009, 2011, 2013 में जीईसी- 1997 द्वारा अनुशंसित कार्यप्रणाली के आधार पर किया गया था और वर्ष 2017 और 2020 में नवीनतम जीईसी-2015 पद्धति के आधार पर इसका पुनः आकलन किया गया।

2. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, राज्य भूजल / नोडल विभाग, जल क्षेत्र से संबन्धित केंद्र और राज्य सरकारी संगठनों सहित संरक्षण/प्रबंधन, शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा जीईसी-2015 पद्धति को अपनाकर भूजल आकलन /पुनर्भरण/संरक्षण आदि से संबंधित कई अध्ययन/ परियोजनाओं को पूरा किया गया है। इन अध्ययनों के परिणाम विभिन्न परामर्शी बैठकों और कार्यशालाओं में प्रस्तुत किए गए और उन पर विचार-विमर्श किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2022 से प्रत्येक जल वर्ष (जून से मई) के लिए भूजल संसाधन आकलन किया जाएगा। उपरोक्त विंदुओं को ध्यान में रखते हुए, नई प्रगति/प्रथाओं/उपकरणों को शामिल करने और आकलन में उपयोग किए जा रहे विभिन्न मानकों को परिष्कृत करने के लिए जीईसी-2015 पद्धति की समीक्षा और संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई।

### 3. भूजल संसाधन आकलन समिति की संरचना

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार ने भूजल संसाधन आकलन पद्धति (जीईसी-2015) की समीक्षा और संशोधन करने और संबंधित विषयों पर ध्यान देने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

1.	अध्यक्ष, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड	अध्यक्ष
2.	सदस्य (आरएम), सीडब्ल्यूसी या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	सदस्य सचिव (सीजीडब्ल्यूए)	सदस्य
4.	निदेशक, एनआईएच, रुड़की या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
5.	भूजल विषयों से संबंधित मुख्य अभियंता / निदेशक पंजाब	सदस्य
6.	भूजल विषयों से संबंधित मुख्य अभियंता / निदेशक उत्तर प्रदेश	सदस्य
7.	भूजल विषयों से संबंधित मुख्य अभियंता / निदेशक महाराष्ट्र	सदस्य
8.	भूजल विषयों से संबंधित मुख्य अभियंता / निदेशक राजस्थान	सदस्य
9.	भूजल विषयों से संबंधित मुख्य अभियंता / निदेशक पश्चिम बंगाल	सदस्य
10.	भूजल विषयों से संबंधित मुख्य अभियंता / निदेशक तमिलनाडु	सदस्य

11.	भूजल विषयों से संबंधित मुख्य अभियंता / निदेशक असम	सदस्य
12.	प्रोफेसर डी आर कौशल, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी दिल्ली	सदस्य
13.	डॉ. प्रवीण के. ठाकुर, प्रमुख, जल संसाधन विभाग, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस), इसरो, देहरादून	सदस्य
14.	डॉ पी नंदकुमारन, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	सदस्य
15.	डॉ एवीएसएस आनंद, पूर्व वैज्ञानिक-डी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	सदस्य
16.	प्रोफेसर के. बी वी एन फणींद्र, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी हैदराबाद	सदस्य
17.	सदस्य (दक्षिण), सीजीडब्ल्यूबी, फरीदाबाद	सदस्य सचिव

नोट:- यदि आवश्यक हो समिति अस्थायी आधार पर अन्य तकनीकी सदस्य (सदस्यों) को शामिल कर सकती है।

#### 4. विचारार्थ विषय: -

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं: -

- भूजल आकलन समिति (2015) द्वारा अनुशंसित कार्यप्रणाली के विवरण को देखने के लिए और भूजल आकलन के लिए वार्षिक आवधिकता के संशोधन सहित भूजल संसाधनों के क्षेत्र में नवीनतम विकास को ध्यान में रखकर संशोधन के लिए आवश्यक पहलुओं पर सुझाव देना। समिति यदि आवश्यक समझे, विभिन्न भूजलवैज्ञानिक स्थितियों और जलवायु क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के आकलन के लिए मौजूदा पद्धति को पुनः तैयार करना, अद्यतन करने या पूरी तरह से एक नई पद्धति की सिफारिश कर सकती है।
- देश के जलोढ़ / मुलायम चट्टानी क्षेत्रों के गहरे जलभृतों में भूजल संसाधनों के आकलन के लिए एक पद्धति की सिफारिश करना।
- भूजल परिदृश्य के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए आकलन इकाइयों के वर्गीकरण की समीक्षा और विभिन्न आकलन इकाइयों के लिए बेहतर शब्दावली निर्धारित करना। (प्रति इकाई क्षेत्र में जल की उपलब्धता, निष्कर्षण के चरण और स्थिरता आदि के आधार पर)।
- समिति विभिन्न देशों द्वारा अपनाई जा रही पद्धतियों का अध्ययन कर सकती है और देश के विभिन्न, विविध भूभागों, जल-भूवैज्ञानिक स्थितियों के अनुकूल एक व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य कार्यप्रणाली का सुझाव प्रस्तुत कर सकती है।
- उपरोक्त से संबंधित कोई अन्य विषय।

#### 5. समय सीमा

समिति इस संकल्प के जारी होने की तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

#### 6. व्यय

समिति के आधिकारिक सदस्यों को टीए/डीए का व्यय उस स्रोत से किया जाएगा जिससे वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं और सह-चयनित सदस्यों (यदि कोई हो) का वहन केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। निजी व्यक्तियों/सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के संबंध में समिति की बैठक (बैठकों) में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक वर्तमान प्रावधानों के अनुसार होगा।

इसे माननीय जल शक्ति मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि प्रकाशित संकल्प की एक प्रति अभिलेख के लिए इस मंत्रालय को भेजी जाए।

आशीष कुमार  
निदेशक (भूजल)

MINISTRY OF JAL SHAKTI  
(DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA  
REJUVENATION)

New Delhi, the 3rd November 2022

RESOLUTION

Sub: Constitution of Ground Water Resource Estimation Committee to review and revise Ground Water Estimation Methodology 2015 (GEC- 2015)

No. T-13014/1/2019-GW—The ground water resource assessment of the country is being carried out jointly by Central Ground Water Board and State Ground Water/Nodal Departments at periodical intervals based on methodology recommended by “Ground Water Resource Estimation Committee (GEC)” constituted by Ministry of Jal Shakti, Government of India. The 1st “Ground Water Resource Estimation Committee (GEC)” was constituted in 1984, then subsequently in 1997 & 2015 to review and revise the methodology incorporating new advancements/practices/tools and also refining the various parameters being used in the assessment. Ground Water Resource of the country was assessed in 2004, 2009, 2011, 2013 based on the methodology recommended by GEC- 1997 and assessment in 2017 & 2020 were carried out based on latest GEC- 2015 methodology.

2. Central Ground Water Board, State Ground Water/Nodal Departments, Central & State Govt. Organisations involved in water sector including conservation/management, Academic Institutions/Universities and NGOs, VOs & others have carried out number of studies/projects related to ground water assessment/recharge/conservations etc. since GEC-2015 methodology was adopted. Results of these studies were presented and deliberated in various consultative meetings and workshops. It has been decided by Ministry of Jal Shakti that from 2022 onwards, Ground Water Resource Assessment will be carried out annually for each water year (June to May). Considering the above points, a need was felt to review and revise the GEC-2015 methodology to incorporate new advancements/practices/tools and also refining the various parameters being used in the assessment.

3. Composition of the Ground Water Resource Estimation Committee

In the view of above, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India hereby constitutes a committee to review and revise Ground Water Resource Estimation Methodology (GEC-2015) and look into related issues. The committee will consist of the following Members:—

1.	Chairman, Central Ground Water Board	Chairman
2.	Member (RM), CWC or his representative	Member
3.	Member Secretary (CGWA)	Member
4.	Director, NIH, Roorkee or his representative	Member
5.	Chief Engineer/Director dealing groundwater subject in Punjab	Member
6.	Chief Engineer/Director dealing groundwater subject in Uttar Pradesh	Member
7.	Chief Engineer/Director dealing groundwater subject in Maharashtra	Member
8.	Chief Engineer/Director dealing groundwater subject in Rajasthan	Member
9.	Chief Engineer/Director dealing groundwater subject in West Bengal	Member
10.	Chief Engineer/Director dealing groundwater subject in Tamil Nadu	Member

11.	Chief Engineer/Director dealing groundwater subject in Assam	Member
12.	Prof D R Kaushal, Department of Civil Engineering, IIT Delhi	Member
13.	Dr. Praveen K. Thakur, Head, Water Resource Department, Indian Institute of Remote Sensing (IIRS), ISRO, Dehradun	Member
14.	Dr P Nandakumaran, Former Chairman, Central Ground Water Board	Member
15.	Dr AVSS Anand, Former Scientist-D, Central Ground Water Board	Member
16.	Prof KBVN Phanindra, Department of Civil Engineering, IIT Hyderabad	Member
17.	Member(South), CGWB, Faridabad	Member Secretary

Note:- The committee may co-opt technical member(s), if necessary, purely on temporary basis.

#### 4. Terms of reference

The terms of reference of the Committee are as follows: -

- i. To look into the details of the methodology recommended by Ground Water Estimation Committee (2015) and to suggest aspects which call for a revision in view of the latest developments in the field of groundwater resources including revision of yearly periodicity for groundwater assessment. The Committee may if considered necessary, refine, update the existing or recommend a new methodology altogether for the assessment of ground water resources in different hydro- geological situations and climatic zones.
- ii. To recommend a methodology for assessment of ground water resource in deeper aquifer in alluvial/soft rock areas of country.
- iii. Review of categorization of assessment units for better representation of ground water scenario and to explore better terminology for different assessment units.(based on water availability per unit area, stage of extraction and sustainability etc)
- iv. Committee may go through methodologies being adopted by various countries and come out with a practical and implementable methodology suiting to diverse, varied terrains, hydro-geological situations of the country.
- v. Any other aspects relevant to the terms referred to above.

#### 5. Time Frame

The Committee may submit its report within 3 months from date of issue of resolution.

#### 6. Expenditure

Expenditure on account of TA/DA to official Members of the Committee will be met from the source from which they draw their salaries and that of co- opted members (if any), will be borne by the Central Ground Water Board. Remuneration for attending the Committee meeting(s) with respect to Private persons/retired Government officers shall be governed by the extant provisions.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister of Jal Shakti.

## ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered that a copy of the Resolution published be communicated to this Ministry for record.

ASHISH KUMAR  
Director (GW)